RNI NO. MPHIN/2022/85285
डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24
Email id: haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

वर्ष 03 अंक 04 | जुलाई 2024 | पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

जून में सामान्य से 11 फीसदी कम हुई बारिश अब जुलाई के पुर्वानुमान पर टीकी नजरें

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। इस साल जून में मानसून ने चिंताएं बढ़ा दी है। समूचे देश में सामान्य से 11 कम बारिश हुई है। यही कारण है कि अब सबकी निगाहें मौसम विभाग के जुलाई के पूर्वानुमान पर टिकी हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त भारत के 50 प्रतिशत हिस्से में बारिश की कमी है। इसका असर सीधे तौर पर कृषि कार्यों पर पड़ा है।

सरकार 2024.25 फसल वर्ष (जुलाई.जून) के दौरान 340.40 मिलियन टन (एमटी) खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन देखने के लिए मौसम विभाग के सामान्य से अधिक पूर्वानुमान पर दांव लगा रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में 1.30 जून के दौरान 147.2 मिमी बारिश हुई, जो महीने के लिए 165.3 मिमी के अपने दीर्घकालिक औसत का 89 प्रतिशत है। देश के आधे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने वाले 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या तो कम या बहुत कम बारिश वाले हैं। दूसरी ओर, 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जून में सामान्य या उससे अधिक बारिश हुई है।

रिपोर्ट में और क्या है?

पिछले महीने, मौसम विभाग ने मानसून की प्रगति कई दिनों तक ठप रहने के बाद जून के लिए अपने वर्षा पूर्वानुमान को सामान्य से संशोधित कर सामान्य से कम कर दिया था। एलपीए के 92 प्रतिशत से 108 प्रतिशत के बीच बारिश को सामान्य की श्रेणी में रखा जाता है। जिन राज्यों में सामान्य या उससे अधिक बारिश हुई है, उनमें असमए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं।

दूसरी ओर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में कम बारिश हुई है। अन्य राज्य जहां सामान्य से कम बारिश हुई हैए वे हैं गुजरात, केरल, झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर।

विभिन्न क्षेत्रों में, दक्षिण प्रायद्वीप में 183.9 मिमी बारिश के साथ 14 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है, मध्य भारत में सामान्य से 14 प्रतिशत कम 147 मिमी बारिश हुई है, उत्तर पश्चिम में औसत से 33 प्रतिशत कम 52.6 मिमी बारिश हुई है और पूर्व और उत्तर.पूर्व क्षेत्र में औसत से 13 प्रतिशत कम 284.9 मिमी बारिश हुई है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

कृषि वैज्ञानिक एसके सिंह के अनुसार जुलाई में चार महीने के मानसून सीजन में सबसे अधिक बारिश होती है और इस महीने अधिक बारिश होने से पिछले साल की तरह जून में हुई कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि खरीफ की बुवाई की गति उम्मीद से कम है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि किसान इस साल जल्दी बुवाई शुरू कर देंगे।

हालांकि, उन्होंने कहा कि मध्य भारत में कई दिनों तक रुके हुए मानसून ने किसानों को जल्दी बुवाई शुरू करने का मौका नहीं दिया। पिछले साल जून में मानसून में 8.5 प्रतिशत की कमी थी, लेकिन जुलाई में 12.6 प्रतिशत अधिक बारिश हुई थी। हालांकि, अगस्त में रिकॉर्ड 36 प्रतिशत कम बारिश ने कर्नाटकए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कई फसलों की पैदावार को कम कर दिया। सरकार ने खरीफ सीजन के लिए खाद्यान्न (चावल, गेहूं, दालें और मोटे अनाज) का लक्ष्य 159.97 मिलियन टन, रबी सीजन के लिए 164 मिलियन टन और जायद (ग्रीष्म) सीजन के लिए 16.43 मिलियन टन निर्धारित किया है।

ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन ने कि रसायनिक एवं कीटनाशको उर्वरको को जीएसटी मुक्त रखने की रखी मांग

केंद्रीय जीएसटी सेक्रेटरी से मुलाकात कर सौंपा मांगपत्र

हलधर किसान. नई दिल्ली। आगामी दिनों में देश का पूर्ण बजट पेश होने से पहले ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन ने भी रसायनिक एवं कीटनाशक उर्वरको को जीएसटी मुक्त रखने की मांग तेज कर दी है। इसी मांग को लेकर ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलन्त्री के नेतृत्व में कृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जीएसटी सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह एवं बंसल मैडम के साथ विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव भेजेंगे।

ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलन्त्री के नेतृत्व में पिछले वर्ष लगातार जीएसटी काउंसिल से कुछ निर्णय को बदलवाने के लिए दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला प्रारंभ किया था उसका रिजल्ट में पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में देखने को मिला है। जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ इंदौर जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने बताया कि बैठक में उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल, आबासाहेब भोकरे, अतुल त्रिपाठी, सत्यनारायण कासट, सुभाष दरक, विपिन कासलीवाल, मधुकर मामडे, राजेंद्र भंडारी, यशवंत भाई पटेल, संजय रघुवंशी, मनमोहन सरावगी के साथ.साथ व्यापारी महासंघ महाराष्ट्र के अशोक शेटे, वाय. जनार्दन राव के साथ.साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल लड्ढा, यश डड्ढा एवं आनंद नाहर भी उपस्थित थे।

इन मीटिंगों में आए सकारात्मक परिणाम

श्री दुबे ने बताया कि पिछले वर्ष लगातार जीएसटी काउंसिल से कुछ निर्णय को बदलवाने के लिए संगठन पदाधिकारियों ने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकार के प्रमुख सचिवों से मुलाकातें की। 19 दिसंबर 2023 को तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री जीएसटी प्रभार पंकज चौधरी के निवास पर मुलाकात की गई। 20 दिसंबर 2023 को केंद्रीय जीएसटी सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह एवं बंसल मैडम के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी।15 जनवरी 2024 को पुनः जीएसटी सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह के साथ हमारे प्रतिनिधिमंडल एवं 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ विचार विमर्श किया गया। 6 फरवरी 2024 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ बीड की तत्कालीन सांसद प्रीतम मुंडे के साथ एक मीटिंग की गई एवं मांग की गई थी कि पुराने ऑडिट पर पेनल्टी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी की समस्या को हल करना एवं खाद एवं कीटनाशक पर से जीएसटी को मुक्त किया जाए।

उपरोक्त चारों मीटिंगों में हमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं जीएसटी सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह से आश्वासन मिला था कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इन सब मुद्दों को गंभीरता पूर्वक रखा जाएगा एवं उनके निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। विगत दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया संगठन के द्वारा उठाई गई सभी महत्वपूर्ण मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें जीएसटी अधिनियम की धारा 73 का तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए वित्तीय वर्ष 17.18, 18.19 और 19.20 के लिए दंड और ब्याज को माफकर दिया गया है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों को जीएसटी मुक्त करने की मांग को गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए मंत्रियों के आधिकारिक समूह के पास सिफारिश भेजी गई है। यदि जीओएम द्वारा उक्त सिफारिश को मान लिया जाता है तो अगस्त माह में होने वाली अगली जीएसटी की बैठक में रासायनिक उर्वरक भी जीएसटी से मुक्त हो सकते हैं।

एजेंसी देना है-

प्रतिष्ठित मासिक समाचार पत्र हलधर किसान/ इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म किसान प्लस टीवी पर कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान, नई तकनिक, योजनाओं के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के समावेश के साथ नियमित रुप से प्रकाशित हो रहा है।

अगर आप भी कृषि पत्रकारिता में रूचि रखते है तो हमारे न्यूज चैनल सहित अखबार से जुड़ने के लिए हमारे वाट्सअप नंबर(88174 02860) या हमारे प्रधान कार्यालय 598, बेगॉस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है।

कृषि में एआई: कंप्यूटर की नजर से भविष्य की खेती की ओर

खेती में नई क्रांति लेकर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानिये कैसे लिया जा रहा काम

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

भोपाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कृषि क्षेत्र में क्रांति लेकर आया है। इसने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को फिर से परिभाषित किया है और कृषि स्वचालन प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त किया है। लगातार बढ़ती खाद्य आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए खेती में सटीक और विकसित तकनीकों को अपनाना अति.आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग फसल की निगरानी, रोग का पता लगाने से लेकर उपज की भविष्यवाणी, सटीक फसल बुआई का समय एवं कृषि के विभिन्न पहलुओं को अनुकूलित करने के लिये किया जा सकता है।

वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि और जलवायु पैटर्न में बदलाव के साथ, किसान डेटा.आधारित निर्णय ले सकते हैं। साथ ही संभावित जोखिमों के बारे में सजग करने हेतु भविष्यवाणी कर सकते हैं और सटीक सलाह से समग्र कृषि प्रक्रिया को आसान कर सकते हैं। यह एक कंप्यूटर संचालित सिस्टम है, जो कृषि में स्वचालन और रोबोटिक्स को अपनाकर शारीरिक श्रम को कम करता है।

आज के आधुनिक दौर में हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की चर्चा है। हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तरह.तरह के प्रयोग हो रहे हैं। खेती.किसानी के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के बारामती जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी से फसलें उगाई गई हैं। बारामती में पहली बार कृषि में किया गया यह प्रयोग सफल भी रहा है। गन्ने के साथ.साथ भिंडी, टमाटर, मिर्च, तरबूज, कद्दू, फूल, पत्तागोभी जैसी फसलें उगाई गई। इसमें हर फसल की योजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। और फसल प्रबंधन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के सेंसर फसलों के बारे में जानने में मदद करते हैं।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न फसलों में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर हैं, जिनसे फसलों के बारे में जानने में मदद मिलती है। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पलाश, हवा का तापमान और हवा की गति और हवा की नमी को मापने की प्रणाली के साथ.साथ वायु रोगों की सूक्ष्म निगरानी के लिए भी सेंसर हैं।

हर आधे घंटे में देता है जमीन की रिपोर्ट

इसके साथ ही इसमें एक सेंसर प्रणाली है जो पानी को मापती है, मिट्टी की लवणता की जांच करती है और मिट्टी में फसलों को प्रभावित करने वाली विद्युत चालकता की भी जांच करती है। यह सिस्टम हर आधे घंटे में जमीन और जमीन के बाहर और हवा में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी सेंसर के जरिए सैटेलाइट को और सैटेलाइट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर को भेजता है। उससे, एआई प्रणाली संबंधित किसान को पर्याप्त जानकारी प्रदान करती है। इस सूचना की मदद से किसान मिट्टी में कितना पानी देना है, कितना उर्वरक देना है, किस प्रकार का उर्वरक देना है और कितना देना है जानकारी पाता है।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी खेती में एआई के इस्तेमाल की पहल की

कृषि के क्षेत्र में एआई का प्रयोग पहली बार किया गया। इस प्रयोग से सफलता भी मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी खेती में एआई के इस्तेमाल की पहल की है और बारामती में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच इस संबंध में प्रयोग चल रहे हैं। हर किसान को सबसे ज्यादा डर रहा है रोगों या वायरस का होता है।

कई बार खेती में रोग दूसरा होता है, लेकिन उसे सही से समझ नहीं पाने की वजह से समय से उसका उपचार नहीं हो पाता है और नुकसान झेलना पड़ता है। एआई की मदद से रोग से समय से पहचानना और उसके उचित इलाज को लागू करना आसान हो जाएगा। इससे खेती की सुरक्षा बढ़ेगी और नतीजा ये होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा।

नियमों की आड़ में नापतौल विभाग के अफसरों की नहीं सहेंगे मनमानी: जिलाध्यक्ष श्री दुबे

बिना सैंपल लिए 11 बीज दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण बनाने पर लामबंद हुए कृषि आदान विक्रेता

हलधर किसान इंदौर। नापतौल विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से आर्थिक राजधानी के रुप में पहचाने जाने वाले महानगर के खाद. बीज के व्यापारी परेशान हैं। खरीफसीजन के बीज नापतौल विभाग के अधिकारी लगातार दुकानों की सैंपलिंग कर रहे है, इतना ही नही बिना किसी सैंपल के प्रयोगशाला में जांच के ही अमानक बता रहे है, जिससे लायसेंसी व्यापारियों में आक्रोश पनप रहा है। गत दिनों 11 दुकानों पर जांच के बाद कृषि आदान को अमानक बताने पर जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ ने आपत्ति जताई है।

बैठक में जताया कार्रवाई का विरोध

जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने विभाग के इस रवैये को लेकर बैठक आहुत की, जिसमें सभी व्यापारी शामिल हुए। बैठक में अध्यक्ष दुबे ने कहा कि व्यापारी नियमों के अनुसार व्यापार कर रहे है, हमेशा कृषि, नापतौल विभाग को सहयोग करते है, लेकिन छोटी-छोटी गलतियों पर भी अधिकारी लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देते हैं। इसे अब व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि व्यापारियों की कोई गलती हो तो उसे नोटिस देकर सुधार करने का मौका दिया जाना चाहिए। व्यापारियों ने कहा कि विभाग के कई अधिकारी बेवजह व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर नियमों का हवाला देकर धौंस जमाते हैं। यदि किसी भी व्यापारी को बेवजह परेशान किया गया तो सभी एकजुट होकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे।

प्रतिबंधित उत्पाद न रखें न बेचें

बैठक में श्री दुबे ने बताया कि हम नियमों का पालन करने वाले व्यापारी है, वर्तमान में कृषि मंत्रालय के द्वारा जो मोनीकुल है जो टेक्निकल है या जो प्रोडक्ट है उनको बैन लगा दिया गया है। ऐसी उत्पाद की बिक्री या भंडारण कतई नहीं करें। जैसे डीडी वीपी, नुवान जैसे फोरेट और भी कई इस प्रकार के उत्पाद है जो मंत्रालय द्वारा शासन द्वारा बंद कर दिए गए हैं। हमें ऐसे प्रतिबंधित उत्पाद को तुरंत बंद कर देना चाहिए।

इस कार्रवाई का हो रहा विरोध

नापतौल विभाग द्वारा नकली और अमानक बीज प्रोडक्ट की जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान प्रोडक्ट पर पैकिंग, वजन, पैकिंग दिनांक, एक्सपायरी, निर्माता का नाम, पता, ई.मेल, कांटेक्ट नंबर, मूल्य आदि देखा जा रहा है। शहर के कुछ प्रतिष्ठानों पर इस तरह की जानकारी प्रकाशित नही होने पर विभाग ने 11 दुकानदारों के खिलाफअमानक और नकली बीज बेचने का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जिस पर संगठन ने आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन का कहना है कि वह विक्रेता है, कमियां पाई गई है तो सैंपलिंग कि जानी थी, प्रयोगशाला में प्रोडक्ट की जांच कराना थी। नापतौल अधिकारी बिना जांच के कैसे इसे नकली और अमानक बता सकते है। यह कार्रवाई व्यापारियों को परेशान कर बदनाम करने जैसी है। इसके खिलाफ सभी व्यापारी एकजुट है। व्यापारियों ने कहा कि विभाग के प्रेसनोट पर अखबारों में भी अमानक और नकली बीज बेचे जाने के समाचार प्रकाशित हुए, जो व्यापारियों को बदनाम करने जैसा कदम है।

विभाग को सैंपल की जांच रिपोर्ट आने तक अमानक बताने का कोई अधिकार नही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी लायसेंसी व्यापारी नापतौल विभाग सहित कृषि आधिकारियों से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे और हमारे जिन साथियों पर जल्दबाजी में प्रकरण बनाए गए है उसे निरस्त कराने की मांग की जाएगी।उक्त मीटिंग में व्यापारी आरआर गुप्ता, आशीष लाठी, चंद्र प्रकाश जैन, जितेंद्र जैन, निखिल जैन, पूनम हार्डिया, किशोर पुराणिक, महेश गुप्ता, अजय गुप्ता, सूरज गुप्ता, विनोद चौहान, गोपाल सांखला, अभिषेक दुबे, सुनील पाटीदार, विवेक वाणी, आशीष जैन, सुखराम पाटीदार उपस्थित रहे।

क्यों नही अपना पा रहे केमिकल फ्री खेती?

वर्तमान में केमीकल फ्री अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है, परंतु फिर भी केमीकल फ्री खेती करने वाले किसानों की संख्या में उतना इज़ाफा नहीं हो पा रहा है, जितना होना चाहिए। जबकि सरकार द्वारा जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के लिए खूब जोर.शोर से प्रचार किया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। फि भी ज़मीनी स्तर पर कोई चमत्कार नहीं हो पा रहा है जैविक खेती को लेकर। आखिर ऐसा क्यों?

सबसे पहला सवाल यह है कि जनता केमीकल फ्री अनाज को अपनाने से क्यों कतरा रही है, जबकि वह जानती है कि बाजार में जो अनाज मिल रहा है वह पूरी तरह से केमीकल पर आधारित है और उनके लिए हानिकारक साबित हो रहा है? दूसरा सवाल है कि क्या केमीकल फ्री या जहरमुक्त अनाज महंगा है? तीसरा प्रश्न यह है कि इसकी क्या गारंटी है कि जैविक किसान केमीकल फ्री अनाज ही दे रहा है?जैविक किसान पर कैसे विश्वास करें? चौथा और आखिरी प्रश्न यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है, जिससे जनता, किसान और सरकार सबको फायदा भी हो और सबको केमीकल फ्री अनाज मिलना सुलभ हो जाए और महंगाई से भी निजात मिल जाए सबको?

तो पहले प्रश्न पर बात करते हैं कि जनता केमीकल फ्री अनाज को अपनाने से क्यों कतरा रही है? अक्सर देखने में यह आता है कि जनता या ग्राहक प्रश्न करते हैं कि भईया ! गेहूं तो केमीकल फ्री ले लेंगे, पर बाकी चीजें कहां से लाएँगे? इसमें ग्राहक जाने.अनजाने उपलब्धता की कमी की ओर इशारा कर रहा है और उपलब्धता के बहाने जो केमीकल फ्री गेहूं मिल रहा है उसे भी लेने से मना कर रहा है। चूंकि केमीकल फ्री खेती करने वाले किसानों की संख्या अभी बहुत कम है, तो उपलब्धता की कमी है इसमें कोई दो राय नहीं है।

अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि क्या केमीकल फ्री उत्पाद महंगा है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ। आपको ज़हरमुक्त अनाज भी चाहिए और वह भी सस्ता यह कैसे संभव है? जबकि वर्तमान में तो आप केमीकल से परिपूर्ण अनाज महंगा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि पहले प्रश्न से साफ जाहिर है कि उपलब्ता की कमी है, तो उपलब्धता की कमी के चलते जहरमुक्त उत्पाद महंगा तो होगा ही। जैसे.जैसे केमीकल फ्री खेती करने वाले किसानों की संख्या और उपलब्धता बढ़ेगी वैसे.वैसे ये उत्पाद भी सस्ते मिलने लगेंगे। यदि ग्राहक और किसान समझदारी दिखाएं तो उपलब्धता और महँगे केमीकल फ्री अनाज की समस्या को आराम से सुलझाया जा सकता है। यदि दोनों ईमानदारी और दृढ़ निश्चय के साथ समझौता करें तो केमीकल फ्री किसान को ग्राहक मिल जाएंगे और ग्राहक को पहले से तय मूल्य में केमीकल फ्री अनाज आसानी से उपलब्ध रहेंगे। इसमें ग्राहक और किसान दोनों की समस्या का निराकरण आसानी से हो जाएगा।अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर कि क्या केमीकल फ्री खेती करने वाले जैविक किसान केमीकल फ्री अनाज ही दे रहे हैं? इसकी क्या गारंटी है? केमीकल फ्री खेती करने वाले जैविक किसान पर कैसे भरोसा करें कि वह हमको वाकई केमीकल फ्री उत्पाद ही उपलब्ध करा रहा है? इसके लिए ग्राहक को चाहिए कि वह जैविक प्रमाणित किसान से खरीदारी करें या उन छोटे किसानों से जो बहुत सालों से प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कर रहे हैं, उनसे सामान लें। यदि इसके बाद भी आपको भरोसा नहीं हो तो आप वर्ष में एक या दो बार इन किसानों के खेत पर भ्रमण करके उत्पादन की जो पद्धति है उसका निरीक्षण करें। इससे आपका किसान के ऊपर विश्वास बढ़ेगा और आपके भ्रम भी दूर होंगे। यह इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अनाज, सब्जी इत्यादि रोजमर्रा की जरूरत हैं और इनके बिना जीवन बहुत मुश्किल है, इसलिए इनका शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण होना हमारे परिवार के स्वास्थ्य हेतु बहुत ही जरूरी है।

चौथा प्रश्न इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या के समाधान की चर्चा करने से पहले हम इसकी पड़ताल कर लेते हैं कि यह समस्या बनी ही क्यों? हरित क्रांति से पहले हमारे देश में केमीकल फ्री खेती ही होती थी। जैसे.जैसे हरित क्रांति ने पूरे भारत देश में पैर पसारे, वैसे.वैसे हमारे देश के अनाज, सब्जियाँ, फल इत्यादि सब विषैले होते गए, और आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जिस देश का इतिहास प्रकृति और मौसम आधारित खेती से भरा पड़ा है, अब उसी देश में जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करने के लिए सरकारों और विभिन्न संस्थाओं को अभियान चलाना पड़ रहा है और किसानों से बार.बार मिन्नतें करना पड़ रहा है कि इस ज़हरीली खेती को छोड़कर हमारे पूर्वजों की गोबर आधारित एवं बहुफसली प्रणाली को अपना लो। तो निष्कर्ष निकलता है कि इस समस्या की असली शुरूआत हरित क्रांति के बाद ही हुई और अब विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है।अंत में इतना ही कहना है कि पहले खुद किसान जो बेशकीमती ज़मीन के मालिक हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वे अपने परिवार को तो कम से कम केमीकल फ्री अनाज या अन्य सामग्री खिलाएं। इतना तो वे कर सकते हैं क्योंकि इनके पास खुद की ज़मीन है। साथ में सरकार जो भरसक प्रयास कर रही है कि देश में जैविक खेती हो, उसको इन किसानों पर ही फोकस करना चाहिए। जब किसान अपने परिवार के लिए केमीकल फ्री खेती करने लगेगा तो धीरे.धीरे देश के बाकी लोगों के लिए भी केमीकल फ्री खेती होने लगेगी। वैसे तो काम कठिन है, परंतु मज़बूत इच्छाशक्ति और सही नीयत के साथ किया जाए तो बहुत सरल है।

संपादकीय

जुलाई में सिर्फ 8 दिन बजेगी शादी की शहनाई, 17 जुलाई से शुरु होंगे चातुर्मास

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

हलधर किसान (ज्योतिष).

शुक्र तारा अस्त होने से पिछले तीन माह से शादी सहित अन्य मांगलिक कार्यों पर लगी रोक जुलाई में खत्म होने वाली है। जुलाई महीने की शुरुआत होते ही एक बार फिर शहनाइयों की धुन सुनाई देने लगेगी, यानी शादी विवाह का सीजन शुरू हो जाएगा। हालांकि यह लंबे समय के लिए नहीं हैं, क्योंकि विवाह मुहूर्त तो 3 जुलाई से शुरू होंगे, पर ये केवल 8 दिन यानी 15 जुलाई तक ही रहेंगे।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन सोनी अजमेर के अनुसार अभी गुरु और शुक्र ग्रह के अस्त रहने की वजह से विवाह मुहूर्त नहीं है। इनमें गुरु 2 जून तो शुक्र 29 जून को उदित होंगे। इसके बाद जब तीन जुलाई से मुहूर्त शुरू होंगे, तो वे केवल आठ दिन के इसलिए होंगे, क्योंकि 16 जुलाई को देवशयनी एकादशी रहेगी। इस दिन से चातुर्मास शुरू हो जाएगा। मुहूर्त फिर चार माह बाद 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी से शुरू होंगे। वैसे भी इस साल के अंतिम माह दिसंबर तक अब केवल 27 दिन ही विवाह की शहनाइयां बजेंगी।

जुलाई में केवल 8 मुहूर्त

जुलाई में 8 दिन के मुहूर्त में शहर और आसपास एक हजार से अधिक जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। जुलाई के बाद सीधे नवंबर व दिसंबर में विवाह होंगे। 23 अप्रैल से शुक्र तारा पूर्व दिशा में अस्त है और 6 मई से बृहस्पति अस्त हो चुके हैं। जुलाई में अंतिम विवाह मुहूर्त 15 तारीख को रहेगा।

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो इस बार 17 जुलाई से शुरू होगा और इसका समापन 12 नवंबर 2024 को होगा। 17 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसके बाद भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। इसके बाद सीधे देवउठनी एकादशी के दिन वो जागते हैं, देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 के दिन रहेगा और इसके बाद से ही शादी ब्याह और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं

मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान विष्णु चार माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में किसी भी तरह का कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास में किए गए मांगलिक कार्य पर भगवान विष्णु की कृपा नहीं होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तो वह अपना सारा काम शिवजी को सौंप देते हैं। जब तक विष्णु भगवान योग निद्रा में रहते हैं, तब तक पूरे संसार का संचालन महादेव करते हैं।

अब बात आती है कि चातुर्मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहींण् चातुर्मास के दौरान शादी ब्याह से लेकर किसी तरह के कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसी प्रकार गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदना, घर बनाना, मुंडन, जनेऊ, भूमि पूजन या नया बिजनेस शुरू करने जैसी कोई चीज चातुर्मास में नहीं होती हैं। चातुर्मास के दौरान अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो हर शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए, कहते हैं कि चातुर्मास में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए।

वर्ग पहेली-4

बाएं से दाएं

1. भैंसा (3)
4. ताम्बूल (2)
7. लालन.पालन (5)
8. समुद्र से संबंधित (4)
10. होश, चेत (2)
11. कोयल (2)
13. संत, महात्मा, मुनि, तपस्वी (2)
14. एक तौल की इकाई (2)
16. कमजोर (3)
18. अर्क, सत (3)
20. बाँग्लादेश की मुद्रा (2)
21. मार्ग, रास्ता (2)
22. कोण (2)
24. पुराणवर्णित एक प्रख्यात मणि (4)
26. सारे शरीर में (मुहावरा) (5)
27. पिटाई (4)
28. सुंदरता (3)

ऊपर से नीचे

2. हिमालय (3)
3. दूर स्थित (3)
4. परिभाषा सम्बंधी (5)
5. नाशए नष्ट हो जाना (3)
6. बस्ती (3)
9. भूरा (3)
12. कूड़ा करकट (3)
15. भगवान श्रीकृष्ण का एक नाम (5)
17. भेदए मुअम्मा (3)
19. साथ में काम करने वाला (4)
22. भुना हुआ मांस (3)
23. भिखारी (3)
25. मतलब, इच्छा, उद्देश्य (3)

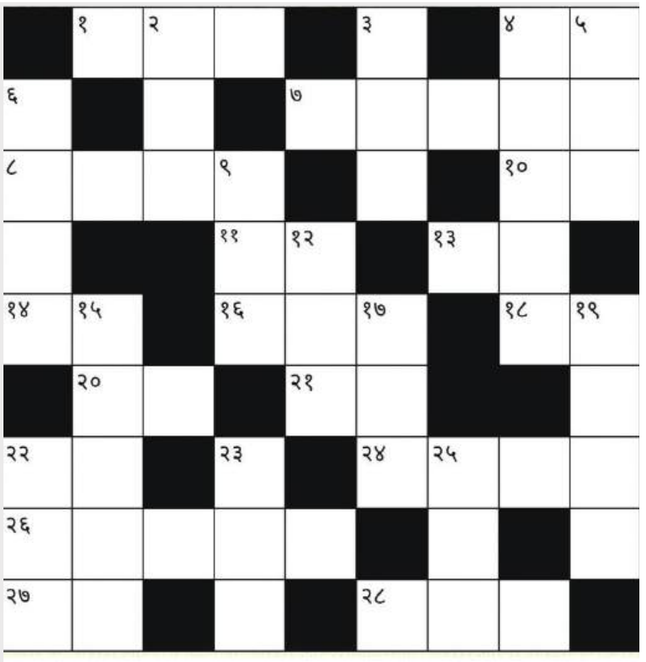

वर्ग पहेली 3 का सही उत्तर

खरीफ सीजन में करें मोटे अनाज की बुआई, मिलेगा मोटा मुनाफा

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

भोपाल. खरीफ फसल का सीजन चल रहा है। प्रदेश में कपास, मिर्च, मक्का, सोयाबीन, धान की फसल इस सीजन की मुख्य फसलों में से एक मानी जाती है, परंतु कई अन्य फसलें भी ह, जो खरीफके सीजन में होती हैं। जिनकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

जी हां हम बात कर रहे हैं उन मोटे अनाजों की जो शरीर के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार भी मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि लोग स्वस्थ रहें।

मोटे अनाजों में टांगुन या कंगनी, कोदो, सांवा, मडुआ और रागी की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। यह कहने में संकोच नहीं होगा कि इसकी खेती कर किसान मालामाल बन सकते हैं।

मोटे अनाजों की खेती के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मोटे अनाज वे अनाज हैं जिसके उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी पक जाते हैं। धान और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन में पानी की खपत बहुत कम होती है। इसकी खेती में यूरिया और दूसरे रसायनों की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होता है। साथ ही किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा भी होता है। खास बात यह है कि मोटे अनाज का सेवन करने से कई तरह की रोग अपने. आप ठीक हो जाते हैं।

करें इन 5 मोटे अनाजों की खेती

1 . टांगुन या कंगनी ये 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है, और एक बीघे के लिए सवा किलो बीज पर्याप्त है। खास बात यह है कि इसमें बहुत कम खाद और पानी की जरूरत पड़ती है। यह ऊंची जमीनों पर भी उगाई जा सकती है

2. मडुआ की बाली गुच्छेदार होती हैं। यह 80 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। मडुआ को सीधी बुवाई करनी है तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई मध्य तक मानसून की बारिश होने पर की जाती है। छिंटकवा विधि की तुलना में सीधी बुवाई से कतारों में बोआई करना बेहतर होता है। लाइन में बुआई करने के लिए बीज दर 4 से 5 किलो एकड़ जरूरत होती है।

3. तीसरी फसल कोदो की हैं। इसका दाना लाल होता है लेकिन बीज हल्के क्रीम कलर के होते हैं। 65 से 100 दिन में तैयार होने वाली फसल है। कोदों की बुवाई का उत्तम समय 15 जून से 15 जुलाई तक है। जब भी खेत में पर्याप्त नमी हो बुवाई कर देनी चाहिए। कोदों की बुवाई अधिकतर छिटकवां विधि से की जाती है।

4. चौथी फसल है रागी, यह छोटे.मोटे अनाजों में सबसे छोटा होता है। बड़े.बड़े होटलों में इसके खीर बनते हैं। 85 से लेकर 110 दिनों में इसकी फसल तैयार होती है। एक बीघे के लिए सवा से डेढ़ किलो बीज पर्याप्त है।

5. 5 वीं फसल है सांवा, यह एक चर्चित अनाज है। यह 60 से 100 दिन में तैयार हो जाता है। खरीफमौसम में सांवा की बुवाई जून से जुलाई के महीने में की जाती है और फसल सितंबर से अक्टूबर के महीने में तैयार हो जाती है।

खेत की कैसे करें तैयारी

किसान ज्वार व बाजरा की खेती के लिए दो से तीन बार कल्टीवेटर से खेत की जोताई कर दें। इसके बाद पाटा लगा दें। वहीं रागी व कोदो के लिए दो से तीन बार हैरो से गहरी जोताई कर पाटा लगाएं।

मोटे अनाज के उन्नत बीज

उन्नत बीज के रूप में बाजरा में पीएसबी .13, एचएचबी. 146, पूसा संकर बाजरा का उपयोग कर सकते हैं। ज्वार में सीएमबी. पांच व छह, रागी में वीएल.252, 149 आरएयू आदि प्रजातियां हैं। कोदो में जेके.1341 व 155 की खेती की जा सकती है।

इस माह में करें बुवाई

बाजरा की बुवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह व ज्वार जून और रागी व कोदो की बोआई जून और जुलाई माह में की जा सकती है। ज्वार और बाजरा में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटी मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं रागी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटी मीटर होनी चाहिए। कोदो में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटी मीटर होनी चाहिए।

मिट्टी की सेहत के लिए फायदेमंद है मछली, क्या आप जानते हैं मछली से बन सकती है खाद!

हलधर किसान. इंदौर। अब तक आपने यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाईजरों के साथ ही गोबर खद के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते है मछलियां भी खाद का काम करती है, मछली की खाद इस कदर प्रभावी है कि वे मिट्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है। वर्तमान में यूरिया खाद का सरकार विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित कर रही है, ऐसे समय में यदि मछली फर्टिलाईजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप खेती.किसानी करते हैं या घर में गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आपके लिए यह खबर खास है। जी हां, फिश फर्टिलाइजर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पौधों में पोषक तत्व को बढ़ाने में काफी असरदार होकर अमृत के समान होता है।

इसके इस्तेमाल करने से पौधे तेजी से बढ़ते भी हैं और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट पौधों में नहीं होता है। इस फर्टिलाइजर को बनाने में मछलियों की हड्डियां और खाल को मिट्टी में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मृत मछलियां चाहिए होती हैं। इन मछलियों को खेत की मिट्टी या गार्डन में दबा दें। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि मछली मिट्टी में पूरी तरह मिल जाएगी। यही मिट्टी फिश फर्टिलाइजर होती है। यह काफी उपजाऊ होगी, जिससे पौधे जल्दी बढ़ेंगे।

कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि फिश फर्टिलाइजर के अनेकों फायदे हैं, क्योंकि मछली की खाद में काफी मात्रा में फास्फेरस होता है। फास्फेरस पौधों की जड़ों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इससे मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाती है। इतना ही नहीं, इस खाद का उपयोग करने से मिट्टी में पानी भी जमा नहीं होता है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम होता है और कैल्शियम, नाइट्रोजन की भी मात्रा होती हैं, जो पौधे के लिए लाभदायक मानी जाती हैं।

अमेरिका में होता था सबसे पहले उपयोग

कई लोगों को सिर्फयहीं मालूम होता है कि मछली सिर्फखाने के काम नहीं बल्कि कई तरह की दवाइयांए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और खाद बनाने के काम आती है। भारत में जब साइंटिस्ट को बेहतर खाद की तलाश थी तो उन्होंने देखा कि अमेरिका के लोग खाद के तौर पर मछली के खाद का उपयोग कर रहे थे, वहां अमेरिका में लोग मक्का उगाने के लिए फसल लगाने से पहले मिट्टी में मछली को रखा।

इसके बाद मक्के की फसल को बोया गया वहां के लोगों ने देखा कि जैसे.जैसे मछलियां सड़ रही थीं। फसल तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद लोगों ने इसे नियमित तौर पर फसल लगाने के पहले फिश फर्टिलाइजर का उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे.धीरे इसका प्रयोग दुनिया भर में किया जाने लगा।

कैसे पौधों को फायदा पहुंचाता है ये खाद

इस खाद में काफी मात्रा में कार्बन होते हैं जो मिट्टी की शक्ति बढ़ाता है। इसके साथ ही मिट्टी में मौजूद कवक और बैक्टेरिया पोषक तत्व को पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इससे पौधे की जड़े मजबूत होती है और पौधा तेजी से बढ़ता है। अगर आप इस तरह के खाद का उपयोग करते हैं तो इसे शुरुआती फरवरी में अपने खेत या गार्डन में डाल सकते है।

पूर्वी और पश्चिमी घाट के मीठे पानी में मिली सूक्ष्म शैवाल की नई प्रजाति 'इंडिकोनेमा'

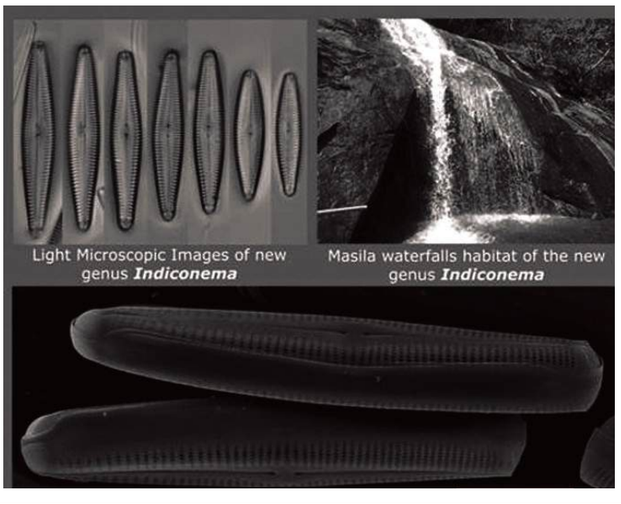

हलधर किसान जल। नई दिल्ली. दुनियाभर के जलीय एवं भूक्षेत्रों में पाए जाने वाले सूक्ष्म शैवाल समूहए जिन्हें डायटम कहा जाता है, की पर्यावरण में अहम भूमिका होती है। हम जो ऑक्सीजन सांस के रूप में ग्रहण करते हैं,उसका करीब एक चौथाई हिस्सा निर्मित करके डायटम हमारे दैनिक जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। पुणे स्थित अघारकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई) के वैज्ञानिकों ने पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मीठे पानी के क्षेत्रों में डायटम की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अध्ययन भारत के विविध क्षेत्रों की जैव विविधता को आकार देने में डायटम के महत्व को रेखांकित करता है। एक नए अध्ययन में भारतीय शोधकर्ताओं ने मीठे पानी के क्षेत्रों में सूक्ष्म शैवालों के नए समूहए जिन्हें डायटम कहा जाता है, का पता लगाया है। डायटम की इस प्रजाति में कई दिलचस्प विशेषताएं हैं, जो इसे गोम्फोनमॉइड समूह के अन्य शैवाल सदस्यों से अलग करती हैं। देश में इसका सीमित वितरण है, जिसे अहमियत देते हुए, नई प्रजाति को इंडिकोनेमा नाम दिया गया है।

क्या होते हैं सूक्ष्म शैवाल समूह

डायटम सूक्ष्म शैवाल हैं, जो वैश्विक ऑक्सीजन का 25 प्रतिशत, यानी हमारे द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन की लगभग हर चौथी सांस का उत्पादन करके हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डायटम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए जाने जाते हैं।

दुनियाभर के महासागरों, जलमार्गों और मिट्टी में पाए जाने वाले डायटम पृथ्वी के बायोमास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। जिस पानी में डायटम मौजूद होते हैं, उससे हर साल 6.7 अरब टन से अधिक सिलिकॉन ग्रहण करते हैं, और महासागरों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं।

किसी भी जल रसायन परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारणए वे जलीय स्वास्थ्य के उत्कृष्ट संकेतक माने जाते हैं। वे जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में कार्य करते हैं।

सूती कपड़े से बना देश का पहला किसान कवच

जानलेवा कीटनाशकों से करेगा बचाव

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली. देश के किसानों को घातक कीटनाशकों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी कवच तैयार किया है। यह सूती कपड़े से बनाया है और इस पर एक ऐसे अणु का इस्तेमाल किया है जो संपर्क में आते ही कीटनाशकों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसका असर जानने के लिए वैज्ञानिकों ने 10 चूहों पर एक शोध भी किया, जिसे नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

बंगलूरू के स्टेम सेल बायोलॉजी, रीजेनरेटिव मेडिसिन संस्थान और सेपियो हेल्थ प्रा. लि. के वैज्ञानिकों ने इस कपड़े को किसान कवच का नाम दिया। इसे पहनने से किसानों के लिए कीटनाशक से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम काफी कम हो सकता है। इस कपड़े पर न्यूक्लियोफाइल अणु का इस्तेमाल किया है, जिसे विकसित करना एक बड़ी चुनौती थी। कम से कम एक साल तक किसान इस कपड़े को धोकर उपयोग में ला सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसान अक्सर फसलों पर छिड़काव करते समय कीटनाशकों के संपर्क में आते हैं। इनमें ऐसे रसायन होते हैं, जिनके संपर्क में आने से इन्सानों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इससे बुखार, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, सांस लेने में समस्याए कंपन के अलावा कुछ मामलों में दृष्टि हानि भी हो सकती है।

केंद्र के बायो टेक्नोलॉजी विभाग ने बताया कि यह किसान कवच कई तरह के कीटनाशकों से लड़ता है। प्रयोगशाला में जांच के समय इस कपड़े का इस्तेमाल चूहों पर किया, जिसमें पता चला कि यह न केवल

तंत्रिका और मांसपेशियों की क्षति जैसे हानिकारक प्रभावों को रोक सकता है, बल्कि उन्हें मृत्यु से भी बचा सकता है।

30 करोड़ किसान होते है प्रभावित

शोधकर्ता डॉ. प्रवीण कुमार वेमुला ने बताया कि देश में हर साल करीब 30 करोड़ किसानों को इससे प्रभावित होने का जोखिम रहता है। वर्तमान में किसानों को नुकसान पहुंचाने से पहले कीटनाशकों को बेअसर करने की कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है।

उर्वरक क्षेत्र में बढ़ी हरित अमोनिया की मांग, सरकार ने बढ़ाया दो लाख टन वार्षिक आवंटन

हलधर किसान. नई दिल्ली। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) वर्ष 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन की 50 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन संचालित कर रहा है। मिशन के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 16 जनवरी 2024 को एनजीएचएम के साइट प्रोग्राम के घटक.प्प् के कार्यान्वयन के लिए योजना से संबंधित दिशा.निर्देश जारी किए थे। इसके मोड.2ए के अंतर्गत हरित अमोनिया उत्पादन की खरीद के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मोड 2, उर्वरक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उक्त दिशा.निर्देशों के अनुसार, मोड 2ए के ट्रेंच 1 के अंतर्गत बोली लगाने के लिए उपलब्ध क्षमता प्रतिवर्ष 5,50.000 टन ग्रीन अमोनिया की थी। इसके बाद, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफइंडिया ने भी लागत आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ग्रीन अमोनिया उत्पादकों के चयन के लिए चयन हेतु अनुरोध जारी किया।

मिशन के कार्यान्वयन की गति तेज होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव की मांग भी बढ़ रही है। उर्वरक क्षेत्र से ग्रीन अमोनिया की मांग में वृद्धि के क्रम में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उर्वरक क्षेत्र के लिए मोड 2ए योजना के अंतर्गत आवंटन में 2 लाख टन प्रति वर्ष की वृद्धि करके योजना से संबंधित दिशा.निर्देश को संशोधित करने का निर्णय लिया है, अर्थात ग्रीन अमोनिया के 5,50.000 टन प्रति वर्ष के मौजूदा आवंटन को बढ़ाकर 7,50.000 टन प्रति वर्ष कर दिया गया है। देश में ग्रीन हाइड्रोजन और इसके उत्पादों की मांग सृजन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 04 जनवरी 2023 को वित्त वर्ष 2029.30 तक 19ए744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। यह स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के भारत के लक्ष्य में योगदान देगा और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के लिए प्रेरणा का काम करेगा। इस मिशन के बारे में कहा जा रहा है कि यह अर्थव्यवस्था को काफी हद तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने के साथ.साथ जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करेगा। इसी के साथ, यह मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन से जुड़ी प्रौद्योगिकी और बाजार को लेकर शीर्ष स्थान तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

सीड बॉल : केन्या की इस पद्धति से बंजर जमीन पर भी आएगी हरियाली

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। खेती में विभिन्न तरह के प्रयोग और नवाचार हो रहे हैं। इसी कड़ी में सीड.बॉल जैसी तकनीक भी काम में ली जाने लगी है। बड़े खेतों के लिए उपयोगी इस तकनीक से खेत में जमीन खोदकर बुआई करने के स्थान पर दूर से सीड बॉल को फेंक पर भी बीज डाले जा सकते हैं। अमेरिका में इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है और बड़े खेतों के साथ वनों में खूबसूरत फूलों वाले पौधों को लगाने के लिए इस तकनीक को काम में लिया जा रहा है। व्यक्तिगत खेत में घूमकर सीड बॉल डालने के अलावा गिलोल या हैलीकॉप्टर से भी इसे छिड़काव की तर्ज डाला जा सकता है। बारिश के मौसम से ठीक पहले डालने से ये सीड बॉल मिट्टी के साथ घुल मिल जाते हैं और इसमें अंकुरण होने लगता है। कुछ समय बाद ये पौध या वृक्ष का रूप भी ले लेते हैं।

कैसे तैयार करते हैं सीड बॉल

सीड बॉल तैयार करने के लिए काली और चिकनी मिट्टी को काम में लिया जा सकता है। इसमें कोलीनाइट, स्मेक्टाइट या बेंटोनाइट को मिलाया जा सकता है। इसके अलावा कंपोस्ट खाद को इसमें मिलाया जा सकता है। इसके बाद पोषक तत्वों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें जरूरत के हिसाब से एक या अधिक बीज डालकर इसे लड्डू की तरह गोल बनाकर सूखने के लिए रख सकते हैं। सूखने पर ये सीड बॉल बन जाती हैं। इसमें एक बार काम में ली गई मिट्टी को दोबारा काम में नहीं लेना चाहिए। इसमें मिट्टी का रंग कुछ भी हो सकता है। वैसे लाल मिट्टी में रेड ऑयरन ज्यादा होता है।

जरूरत के हिसाब से बारिश के मौसम या सर्दियों में भी इसे खेत या जंगल में वनारोपण के लिए डाल सकते हैं। वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार इन बॉल को हाथों से खेत में फेंक कर बुआई की जा सकती है। बड़े जंगलों में इसका इस्तेमाल करना है, तो हेलीकॉप्टर या प्लेन से भी छिड़काव किया जा सकता है।

उन्नत किस्म के बीज

सीड बॉल तैयार करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्थानीय बीजों को भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन वे जीवाणु रहित और रोगरोधक होने चाहिए, ताकि कोई शिकायत न रहे।

मनुष्यों और जीवों के जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन गैसे के लिए पेड़ों की जरूरत है, लेकिन तकनीक और बिल्डिंग बढ़ने के साथ ही पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। दुनियाभर के कुछ देश इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें केन्या भी एक देश है, जो पेड़ों को बढ़ावा देने के लिए सीड बॉल्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये सीड बॉल्स क्या होते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि ये सीड बॉल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं।

सीड बॉल्स

सबसे पहले ये जानते हैं कि सीड बॉल्स आखिर क्या होते हैं। जैसा की नाम है सीड बॉल्स यानी एक ऐसा बॉल जिसमें बीज होता है। दरअसल केन्या अपने यहां पर चारकोल से लिपटे हुए बीजों वाले बॉल का इस्तेमाल हरियाली बढ़ाने के लिए कर रहा है। चारकोल में लिपटे हुए बीजों को गुलेल और हेलिकॉप्टर की मदद से दूर तक फेंका जाता है। वहीं बारिश होने पर चारकोल में मौजूद बीज से पौधे पनपने की शुरुआत होती है। जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में सीडबॉल्स केन्या नाम के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत टेडी किन्यानजुई और एल्सन कार्सटेड ने की थी। सीडबॉल को एक सफल प्रयोग माना गया और भारत समेत कई देशों में इससे हरियाली वापस लाने की कोशिश की जा रही है।

मिट्टी की बजाय चॉरकोल क्यों

अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब पेड़ मिट्टी में होते हैं, फिर चॉरकोल वाले सीड बॉल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? बता दें कि इसे गर्म मौसम में मैदानों में फेंका जाता है। वहीं बीजों पर चारकोल को लगाने के पीछे का कारण है कि केवल बीजों को छोड़ने पर उसे चिड़िया और दूसरे जीव खा जाते हैं। लेकिन जब इस पर चारकोल लिपटा होता है, तो यह सुरक्षित रहता है। वहीं जब बारिश आती है तो बॉल में नमी बढ़ती है और बीज अंकुरित होना शुरू होता है। इस तरह बीज से पौधा तैयार हो जाता है। आपने देखो होगा कि हर सीडबॉल में एक बीज होता है। इस बीज के ऊपर चारकोल को चढ़ाकर गेंद जैसा आकार दिया जाता है। ये आकार में एक सिक्के जितने होते हैं।

ऐसे इलाकों में जहां बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है वहां सीड बॉल कॉन्सेप्ट का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रयोग को पहले भी कई बार अजमाया गया है और यह सफल रहा है। जब बाढग्रस्त क्षेत्रों में पानी उतरने के बाद मिट्टी गीली रहती है तब इस तकनीक से मिट्टी के गोले बनाकर उसमें बीज डालकर खेत में फेंक दिया जाता है या मिट्टी में बीज को दबा देना होता है।

यह तकनीक ऐसे इलाकों के लिए कारगर है जहां प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट हो जाती है। तब इस तकनीक के द्वारा फसल उगाई जा सकती है। भारत में अनेक लोग इस विधि से खेती करते है। भारत के लोगों ने इसे सबसे पहले अपनाया है इसलिए भारत में यह इस विधि का प्रणेता फार्म के रूप में जाना जाता है। इसे हम ऋषि खेती के नाम से करते हैं।

देश के बड़े.बड़े बांधों में पानी का स्तर गिरा आंध्र.बिहार की स्थिति सबसे खराब

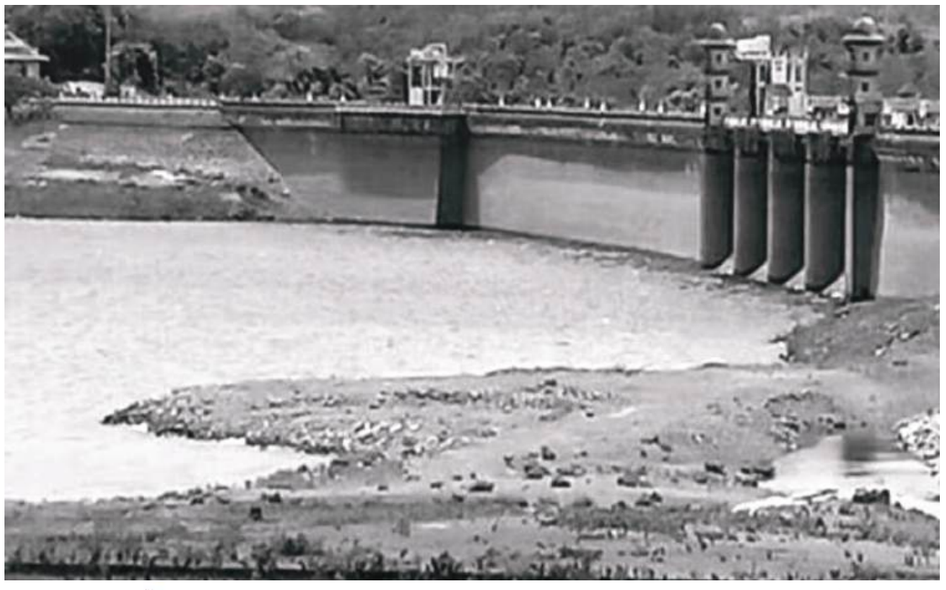

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि लगातार 38वें सप्ताह देश के प्रमुख 150 जलाशयों में भंडारण स्तर में गिरावट आई है। इसका बड़ा कारण दक्षिण.पश्चिम मानसून से अब तक 19 प्रतिशत कम बारिश कम होना है।

सीडब्ल्यूसी ने 150 प्रमुख जलाशयों में भंडारण की वर्तमान स्थिति पर अपने साप्ताहिक बुलेटिन में कहा कि स्तर 178.784 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के 20 प्रतिशत से घटकर 36.368 बीसीएम रह गया है। इस वर्ष भंडारण पिछले वर्ष के स्तर का 78 प्रतिशत और सामान्य का 85 प्रतिशत है।

मध्य प्रदेश में भंडारण सामान्य से नीचे गिरने के साथ, केवल पांच राज्यों में सामान्य से अधिक भंडारण है। सामान्य से कम भंडारण वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर हैए जहां स्तर सामान्य से 78 प्रतिशत कम है। बिहार सामान्य से 69 प्रतिशत कम भंडारण के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु में यह 48 प्रतिशत है।

क्या असर पड़ा?

जलाशयों में कम भंडारण और दक्षिण.पश्चिम मानसून के दो दिन पहले ही दस्तक देने के बाद से ही इसकी अनुपस्थिति ने खरीफकी बुआई में देरी कर दी है। धानए मोटे अनाज, तिलहन और दलहन जैसी प्रमुख फसलों को इसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 27 जून तक मानसून 19 प्रतिशत कम था। क्रेड्यूस के संस्थापक शैलेंद्र सिंह राव ने कहा कि मानसून का वितरण एक समान नहीं रहा है। उन्होंने कहा, जहां कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, वहीं अन्य में कम बारिश हुई है।

आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिणी क्षेत्र में 16 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में 21 प्रतिशत कम बारिश हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीफ फसलों के लिए महत्वपूर्ण मध्य और उत्तर.पश्चिमी क्षेत्रों में क्रमशः 22 प्रतिशत और 44 प्रतिशत कम बारिश हुई है। आईएमडी ने कहा कि अगले 2.3 दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

आंकड़े क्या कहते हैं?

जून 2023 में उभरने वाले अल नीनो, जिसके परिणामस्वरूप देश का एक.चौथाई हिस्सा सूखे की चपेट में आ गया थाए समाप्त हो गया है, लेकिन समुद्र की सतह का तापमान गर्म बना हुआ है, जिससे मानसून की प्रगति प्रभावित हो रही है। 150 प्रमुख जलाशयों में से 138 में भंडारण क्षमता के 50 प्रतिशत से नीचे है। इनमें से 126 में स्तर 40 प्रतिशत से नीचे है।

उत्तरी क्षेत्र में, सभी 10 जलाशयों में स्तर 40 प्रतिशत से नीचे है।

हिमाचल, पंजाब और राजस्थान में भंडारण क्रमशः तीन प्रतिशत, 36 प्रतिशत और 20 प्रतिशत सामान्य से नीचे है। कुल मिलाकर, क्षेत्र का जल संग्रहण 19.663 बीसीएम क्षमता का 27 प्रतिशत यानी 5.239 बीसीएम था।

दक्षिणी क्षेत्र के 42 जलाशयों में इस सप्ताह स्थिति अपरिवर्तित रही, जहां जल स्तर 53.334 बीसीएम क्षमता का 16 प्रतिशत यानी 8.322 बीसीएम था।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा, कर्नाटक में जल संग्रहण सामान्य से 30 प्रतिशत कम और तेलंगाना में सामान्य से 4 प्रतिशत कम था।

पूर्वी क्षेत्र के 23 जलाशयों में से 15 में जल स्तर क्षमता के 40 प्रतिशत से नीचे था। 20.43 बीसीएम क्षमता में से जल स्तर 17.83 प्रतिशत यानी 3.643 बीसीएम था।

पश्चिम बंगाल (-35 प्रतिशत) (त्रिपुरा -16 प्रतिशत) और नागालैंड (-13 प्रतिशत) सभी में जल संग्रहण सामान्य से कम था।

पश्चिमी क्षेत्र में भी सभी 49 जलाशयों में भंडारण क्षमता के 50 प्रतिशत से नीचे चला गया। महाराष्ट्र में यह स्तर सामान्य से 19 प्रतिशत कम रहा। कुल मिलाकर जलाशयों का स्तर 37.130 बीसीएम क्षमता का 20.12 प्रतिशत यानी 7.471 बीसीएम रहा।

मध्य प्रदेश में गांधी सागर भंडारण को छोड़कर मध्य क्षेत्र के शेष 25 जलाशय क्षमता के आधे से भी कम भरे हुए थे। कुल क्षमता 48.227 बीसीएम में से भंडारण 11.693 बीसीएम यानी 24 प्रतिशत था।

खेत की अच्छी सेहत के लिए मिट्टी परीक्षण जरुरी

हलधर किसान (मयंक अत्रे)। किसानों को उनकी मेहनत का फल तब बेहतर मिलता है, जब वह खेती के लिए फसलों के सहीं बीजों का चयन करता है,लेकिन ये भी सच है की बेहतर बीज भी तब ही बेहतर उत्पादन दे पाएंगे, जब खेतों की मिट्टी स्वस्थ्य हो, असल में खेतों की मिट्टी का स्वस्थ्य होना बेहद ही जरूरी होता है, लेकिन किसान मिट्टी की सेहत की चिंता किए बिना ज्यादा उपज के चक्कर में अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके खेती करते हैं, इससे धीरे.धीरे खेत की उर्वरता कम होती जाती है।

कुल मिलाकर मिट्टी बीमार हो जाती है। ऐसे में जरूरी है की खेती से पहले मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। मिट्टी की जांच की जरूरत को लेकर समय. समय पर कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही कृषि विभाग और कृषि मंत्रालय एडवाइजरी जारी करता रहा है। मिट्टी की सेहत में सुधार के लिए उसकी जांच जरूरी है। जांच से ही पता चलता है की मिट्टी में आखिर किन तत्वों की कमी या अधिकता है, जिससे खेती को कितना नफा या नुकसान जैसी बातें पता चल सकती हैं। मिट्टी की जांच के लिए इसके नमूने प्रयोगशाला में भेजने होंते हैं। इस तरह की जांच के लिए सरकारी स्तर पर तो लैब हैं ही, लेकिन अब सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं और प्राइवेट संस्थाए भी आगे आ रही हैं। जहां किसान अपने खेतों की मिट्टी के नमूने भेज कर खेतों में किस पोषक तत्व की कमी है या अधिकता इसके बारे में जानकारी ले सकते है।

खेतों को तेजी से उपजाऊ बनाते है केचुएं

शोधकर्ताओं ने कहा है कि केंचुए जब सक्रिय होते हैं, तो मिट्टी और पौधों को अपने बलगम में उत्सर्जित नाइट्रोजन के माध्यम से तेजी से उपजाऊ बनाते हैं। इससे पहले माना जाता था कि पोषक तत्वों के चक्र में केंचुए जैसे मिट्टी के जीवों की भूमिका लाभदायक तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष के साथ.साथ धीमी भी है। शोधकर्ताटों का कहना है कि अब तक हमने माना था कि इसमें धीमी अपघटन प्रक्रियाएं और माइक्रोबियल साइकिलिंग शामिल है। लेकिन हमारे नए प्रयोगों से पता चलता है कि नाइट्रोजन की गतिविधि मिट्टी के जीवित जीवों से लेकर पौधे तक बेहद तेज हो सकते हैं।

मिट्टी में केंचुए की उपस्थिति को पहले से ही लंबे समय में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जानी जाती है। जो कि उनके खोदने और खाने के माध्यम से होती है जो मिट्टी की अच्छी संरचना बनाती है और नाइट्रोजन को छोड़ती है इस तरह मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों में बंद हो जाती है। प्रयोगशाला और क्षेत्र की स्थितियों के तहत, आयरलैंड, जर्मनी और चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने स्थिर आइसोटोप ट्रेसर नामक एक विधि का उपयोग करके केंचुओं से मिट्टी, गेहूं के पौधों और हरी मक्खियों या ग्रीनफ्लाई में पोषक तत्वों के हस्तांतरण का पता लगाया। केंचुआ से उत्पन्न नाइट्रोजन को ग्रीनफ्लाई ने प्रयोगशाला परिस्थितियों में केवल दो घंटे में और खेत से 24 घंटे के बाद में प्राप्त कर लिया था।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक खेती से एमएसपी तक राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद में कही बड़ी बातें

हलधर किसान,

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में मोदी सरकार के अगले 5 सालों का विजन सामने रखा। राष्ट्रपति का अभिभाषण दरअसल सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड और वर्क प्लान ही होता है। इसमें आने वाले बजट का संकेत छिपा था, तो कांग्रेस के लिए आपातकाल जैसे चुभने वाली बात का भी जिक्र था। राष्ट्रपति के जरिए संसद में रखे गए मोदी सरकार के इस प्लान में महिलाओं, युवाओं, रक्षा, विदेश, खेती.किसानी पर सरकार की प्लान का संकेत मिलता है।

राष्ट्रपति ने इस दौरान गांव समाज से लेकर किसानों, महिलाओं और युवाओं तक की बात की। पीएम किसान सम्मान निधि का जिक्र किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और फसलों की एमएसपी को लेकर भी अपनी बात रखी।

-पीएम किसान सम्मान निधि का जिक्रकिया- राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा किसान अपने छोटे खर्चे पूरे कर सके, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दी जा चुकी है। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरूआती दिनों में ही किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है।

- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिएः राष्ट्रपति ने कहा, आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने की भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी।

- पोषण से लेकर सस्टेनबल एग्रीकल्चर तक समाधान दे रहेः राष्ट्रपति ने कहा कि आज का भारत, दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है। विश्व.बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं।

- हरित उद्योग को बढ़ावा दे रहेः राष्ट्रपति मुर्मू ने हरित युग का जिक्र किया। बोलीं, आने वाला समय हरित युग का है। मेरी सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे हरित जॉब भी बढ़े हैं। हरित ऊर्जा हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे पर हम बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोरः राष्ट्रपति ने कहा, हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हर वैल्यू पर बहुत जोर दिया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों डेयरी और मछली पालन आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, एफपीओ और कृषि जैसे सरकारी संगठनों का बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की समस्या भंडारण को लेकर होती है, इसलिए हमारी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है।

- दलहन.तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए कदम रू राष्ट्रपति ने दलहन.तिलहन का जिक्र किया। बोलीं, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से आत्मनिर्भर हों और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, यह सोचकर नीतियां बनाई गई हैं। भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दी जा रही है। बाजार में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हैए इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है।

- महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरूआतः राष्ट्रपति ने कहा, महिला नीत विकास के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरूआत की है। देश की नारीशक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आज उनके पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ताकत है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का एक व्यापक अभियान चलाया है। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े और उनका सम्मान बढ़े।

उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत हजारों सेल्फहेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं, ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरी सरकार ने हाल में ही कृषि सखी कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके तहत अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 30 हजार महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं।

- विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्वः राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई योजना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ.साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

- मानवता के विरुद्ध टेक्नॉलॉजी का गलत उपयोग बहुत घातक- राष्ट्रपति ने कहा कि आज के समय में टेक्नॉलॉजी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इस प्रवृत्ति को रोकें, इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजें।

-भारत मानवता को बचाने में आगे रहाः राष्ट्रपति बोलीं, मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत, विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। मानव.केंद्रित अप्रोच रखने की वजह से भारत आज किसी भी संकट के समय प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता और वैश्विक दक्षिण की बुलंद आवाज बना है। कोरोना का महासंकट हो, भूकंप जैसी कोई त्रासदी हो या फिर युद्ध की स्थितियां, भारत मानवता को बचाने में आगे रहा है।

मप्र बजट: किसानों को 3.65 लाख करोड़ के बजट में अटल कृषि योजना प्राकृतिक खेती फसल बीमा योजना में मिला 17 हजार 512 करोड़ रुपए का फंड

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला बजट उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया। विधानसभा में साल 2024.25 का बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत मिशन को आगे बढ़ाने में एमपी के योगदान देने के लिहाज से प्रस्तुत किया गया है। बजट में कई ऐसे प्रावधान रखे गए हैं, जो कृषि, स्वास्थ्य, चिकित्सा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सामाजिक, अधोसंरचना क्षेत्र ऊर्जा में सरकार ने विशेष प्रमुखता दी है। इस बजट का आकार 3 लाख करोड़ से अधिक रहा।

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं में बंपर सौगातें दी है। जिससे प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचेगा। इन प्रमुख योजनाओं में सीएम किसान कल्याण योजना, पीएम फसल बीमा योजना, अटल कृषि ज्योति योजना भी शामिल है। इसके अलावा भी ग्रामीण परिदृश्यों को बेहतर करने के लिए भी घोषनाएं की गई हैं।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य राज्य के किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और उनकी आजीविका में सुधार करना है। योजना के तहत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साल 2024 में एमपी सरकार द्वारा जारी बजट में इस योजना के लिए 4 हजार 900 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्तर की फसल बीमा योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाली फसल हानि से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के लिए प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा 2 हजार 001 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।

अटल कृषि ज्योति योजना

अटल कृषि ज्योति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के किसानों को बिजली की सब्सिडी प्रदान करके कृषि सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता और किफायती दर सुनिश्चित करना है। इसके लिए एमपी सरकार ने 5 हजार 510 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।

डेयरी दुग्ध उत्पादकों को सौगात

मध्य प्रदेश सरकार डेयरी दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए कई कदम उठा रही है। मोहन सरकार ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और आजिविका में बढोत्तरी के लिए अपने बजट में 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

सरकार का बजट किसानों के लिये है कल्याणकारी: कृषि मंत्री श्री कंषाना

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि सरकार का बजट किसानों के लिये कल्याणकारी और हजारों करोड़ की सौगात देने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री देवड़ा का विधानसभा में प्रस्तुत किये गये बजट में किसानों को दी गई 17 हजार 512 करोड़ रूपये की सौगात के लिये आभार माना है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में निरंतर फैसले ले रही है। इसकी झलक आज के बजट में भी स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही है।

मध्यप्रदेश सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024.25 के बजट में किसानों के लिये विभिन्न योजनाओं में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। बजट में प्रमुखता से अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5510 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4900 करोड़, मप्रविम द्वारा 5 एचपी के कृषि पम्पों/ थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निः शुल्क विद्युत प्रदाय के लिए प्रतिपूर्ति के लिए 2475 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ और मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि मंत्री ने बताया कि अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द के लिए 521 करोड़, फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के लिए 396 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 266 करोड़, सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट के लिए 235 करोड़ और ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए 208 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने विश्वास जताया कि सरकार के द्वारा किये गये बजट प्रावधान से खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने और किसानों को समृद्ध करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

- प्रदेश में पहली बार 03 लाख 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट की यह विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। किसी भी विभाग की अपेक्षित राशि को कम नहीं किया गया, अपितु सभी विभागों के आवंटन में वृद्धि की गई है।बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान सहित सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान . **मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव**

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन।.RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।